



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022024-252269  
CG-DL-E-21022024-252269

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 772]  
No. 772]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2024/फाल्गुन 2, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024/PHALGUNA 2, 1945

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

**का.आ. 809(अ).—**जबकि मेसर्स टोरेट पावरग्रिड लिमिटेड (टोरेट पावर लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम) जिसका पंजीकृत कार्यालय समन्वय, 600, तपोवन, अंबावाडी, अहमदाबाद, गुजरात - 380015 है, ने “चरण II- भाग - डी के तहत खावड़ा पीएस में 4.5 GW आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए ट्रांसमिशन योजना की स्थापना” के तहत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA Division/160-161 I/26897/2023 दिनांकित 23.03.2023 के द्वारा “चरण II- भाग - डी के तहत खावड़ा पीएस में 4.5 GW आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए ट्रांसमिशन योजना की स्थापना” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स टोरेट पावरग्रिड लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 11.07.2023, राजस्थान पत्रिका (हिंदी में) दिनांक 11.07.2023, दिव्य भास्कर (गुजराती में) दिनांक 11.07.2023, सन्देश (गुजराती में) दिनांक 11.07.2023 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 05.08.2023 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स टोरेट पावरग्रिड लिमिटेड ने 27.12.2023 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन

की तारीख से 2 महीने के भीतर 6 टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसका संतोषजनक उत्तर दिया गया है और उसके बाद कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत चरण II- भाग - डी के तहत खावड़ा पीएस में 4.5 GW आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए ट्रांसमिशन योजना की स्थापना के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. 400 के.वी. पिराना (पीजी) - पिराना (टी) लाइन का अहमदाबाद सबस्टेशन में लूप इन लूप आउट तथा पिराना (पीजी) - पिराना (टी) टावर लाइन की री-कंडक्टिंग।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन गुजरात प्रदेश के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव	तहसील	ज़िला
ग्यासपुर, पिपलज, पिपलज जूना, पिपलज नवा	वटवा /दस्क्रोई/ अहमदाबाद शहर	अहमदाबाद
लांभा, पिराना, कमोद, वणझार, आशापुर, बाकरोल, बदराबाद, ओड, नकलंग, पालडी कांकज, विसलपुर, कासिन्दा, नाना छापरा, मिरोली, भात, छापरा, जूनापुरा, नवापुरा, टिम्बा	दस्क्रोई	अहमदाबाद
मदनपुरा, बदरखा, सरोडा, चलोडा, रिदपुरा, वासणा केलिया, शेखडी	धोलका	अहमदाबाद
काविठा, राशम, जुवाल-रूपावती, सालिजडा आर.एस., सालिजडा, रनोडा, बावला, रूपाल, झेकडा, सिंधराज, केराला, कोचरिया, हसननगर, आदरोडा, वासणा (ना), वासणा डेढाल, डेढाल, बापुपुरा, छवासर, कवला, जुवाल, सांकोड	बावला	अहमदाबाद
हाथीपरा, माणकोल, कुबा, कुंडल, रेथल, मेलासणा, पावनपर, लीलापर, मखियाव, ददुका, बकराणा, झोलापुर	साणंद	अहमदाबाद
ओगन	विरमगाम	अहमदाबाद

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं।-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।

- vi. मेसर्स टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि उपरोक्त शिरोपरि लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त शिरोपरि लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है। आवेदक को उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये, जैसा भी मामला हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है।

[फ़ा. सं. 25-16/6/2024-पीजी]

दीपक राव, निदेशक (पीजी)

**MINISTRY OF POWER****ORDER**

New Delhi, the 20th February, 2024

**S.O. 809(E).**—Whereas M/s Torrent Power Grid Ltd (a Joint venture of Torrent Power Ltd. and Power Grid Corporation of India Ltd.), the applicant, with its registered office at Samanvay, 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad, Gujarat-380015, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under “Evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D”.

And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its letter CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division/160-161 I/26897/2023 dated 23.03.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead transmission line covered under “Evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D”.

M/s Torrent Power Grid Ltd had published notice for transmission scheme in local newspapers The Indian Express (in English) dated 11.07.2023, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 11.07.2023, Divya Bhaskar (in Gujarati) dated 11.07.2023, Sandesh (in Gujarati) dated 11.07.2023 and in weekly Gazette of India dated 05.08.2023 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Torrent Power Grid Ltd. has submitted an affidavit dated 27.12.2023 declaring that 6 observations/representations were received within two months from the date of publication in the official gazette of Government of India, the same have been answered by M/s Torrent Power Grid Ltd. and no further observation/representation was received.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric “Evacuation of 4.5 GW RE injection at Khavda PS under Phase II- Part D”. The following overhead line is covered under this scheme:

1. LILO of Pirana (PG) – Pirana (T) 400kV line at Ahmedabad S/s along with re-conductoring of Pirana (PG) – Pirana(T) line.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat:

Name of villages	Tehsil	District
Gyaspur, Piplaj, Piplaj Juna, Piplaj Nava	Vatva/Daskroi/ Ahmedabad City	Ahmedabad
Lambha, Pirana, Kamod, Vanjhar, Ashapur, Bakrol, Badrabad, Od, Naklang, Paldi Kankaj, Visalpur, Kasindra, Nana Chhapra, Miroli, Bhat, Chhapra, Junapura, Nawapur, Nawapura, Timba	Daskroi	Ahmedabad
Madanpura, Badarkha, Saroda, Chaloda, Ridpura, Wasna Keliya, Shekhadi	Dholka	Ahmedabad

Kavitha, Rasham, Juwal-Rupawati, Salijada, Saljada RS, Ranoda, Bavla, Rupal, Jhekada, Sindharaj, Kerala, Kochariya, Hasannagar, Adroda, Wasna (Na), Wasna Dhedral, Dhedral, Bapupura, Chhabasar, Kavala, Juval, Sakod	Bavla	Ahmedabad
Hathipara, Mankol, Kuba, Kundal, Rethal, Melasna, Pavanapar, Lilapar, Makhiyav, Dhadhuka, Bakrana, Jholapur	Sanand	Ahmedabad
Ogan	Viramgam	Ahmedabad

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Torrent Power Grid Ltd for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Torrent Power Grid Ltd shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line ) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F.No. 25-16/6/2024-PG]

DEEPAK RAO, Director (PG)